निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डिजिटल शासन की स्थापना	शासन के कार्यो में ऑनलाइन कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना	15000	मंत्रालय के समस्त विभागों में ऑनलाइन नस्ती/डाक प्रचालन	1. डिजिटल सचिवालय एप्लीकेशन 2.0 का क्रियान्वयन 2. मंत्रालय के समस्त विभागों में अवकाश प्रबंधन, अचल सम्पत्ति विवरण, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का ऑनलाईन क्रियान्वयन किया गया	15000	
2.	एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट योजना	ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभागों की निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं कुशल बनाना	33800	विभिन्न विभागों तथा उनकी एजेंसियों को निविदा कार्य हेतु ऑनलाईन सुविधा	वर्तमान में समस्त विभागों को एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के अंतर्गत ऑन-बोर्ड किया जा चुका है, जिसमें शासकीय निविदाओं का कार्य किया जा रहा है । इस परियोजना के अंतर्गत अब तक 75231 करोड़ रूप्ये की लगभग 33774 से अधिक निविदा प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है एवं 10992 ठेकेदारों को ऑन-बोर्ड किया जा चुका है ।	29257	
3.	मुख्यमंत्री डैशबोर्ड याजना	शासन के विभागों के प्रदर्शन की समेकित समीक्षा	13372	कृषि, स्कूल शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास तथा जल संसाधन विभाग की समीक्षा हेतु सॉफ्टवेयर का विकास एवं संचालन	प्रदेश स्तर पर विभागों व परियोजनाओं के आंकड़ों का एकत्रण सम्पन्न तथा डेशबोर्ड का मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा नियमित उपयोग किया जा रहा है ।	11834	

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निवेशकों को आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	170000	सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना एवं राकजगार करने हेतु निवेशकों को आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	10 निवेशकों को रूप्ये 228.40 करोड़ का निवेश स्वीकृत किया गया है । कुल 5801 रोजगार सृजित होंगे ।	88375	
5.	स्वान परियोजना	छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यालयों को जोड़ने हेतु सूचना तंत्र का निर्माण	212300	राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर सभी कार्यालयों को सूचना आदान प्रदान हेतु कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	राज्य के जिला, तहसील एवं विभागों में कुल 2030 सीानों पर स्वान से उपलब्ध की गई कनेक्टिविटी का संचालन एवं संधारण किया गया है तथा कुल 2514 विडियों क्लिंसिंग आयोजित की गई ।	212220	
6.	ई-जिला परियोजना	शासन की प्रमुख जी.2सी. सेवाएँ, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु सॉफ्टवेयर एवं अधोसंरचना का विकास	76590	विभागों को जी.2सी. नागरिक सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान करना	लगभग 34.91 लाख आवेदन प्रापत हुआ है, जिसमें से 32.56 लाख आवेदन के सर्टीफिकेट निराकृत किये गये है ।	38295	
7.	कोर इनक्यूबेटर-सह-एक्सेलरेटर संस्थान	राज्य में स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देना	42200	एक सशक्त इनक्यूबेटर-सह-एक्सेलरेटर की स्थापना	राज्य में 91 स्टार्टअप में 400 से अधिक रोजगार सृजित कये गये ।	0	

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	नागरिक संबंध केन्द्र योजना	ाासन की जनहित की योजनाओं के आधार पर समीक्षा	63700	एक कॉल सेंटर की स्थापना एवं समस्त हितग्राहियों के समेकित डेटाबेस का विकास कर शासन की महत्वपूर्ण हितग्राही मूलक योजनाओं का 'फीडबैक' लेना	लगभग 4 लाख नागरिकों की प्रतिक्रिया संकलित की गई है ।	31400	
9.	सेन्ट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फार इन्फ्रास्ट्रक्चर	राज्य के प्रमुख अधोसंरचना निर्माण की परियोजनाओं के कियान्वयन की नियमित निगरानी एवं समीक्षा	45948	लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के प्राजेक्ट्स की समीक्षा हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण एवं मॉनिटरिंग टीम की स्थापना	पीडब्ल्यूडी, सीजीआरडीसी, एएनवीपी, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीटीसीएलं विभागों हेतु निम्नानुसार कार्य सम्पन्न हुए- 1. ए.एस.आई.एस.-टूबी रिर्पोट एवं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन रिपोर्ट का निर्माण किया गया । 2. सी.पी.एम.एस. हेतु कस्टमाईजेशन एवं टेम्पलेट निर्माण का कार्य किया गया है ।	43651	
10.	कौशल विकास एवं प्लेसमेंट हेतु अनुदान	आईटी एवं आईटीईस के क्षेत्र में युवाओं का कौशल उन्नयन	33800	आईटी एवं आईटीईस के क्षेत्र में युवाओं का कौशल उन्नयन	कुल 18342 युवाओं का मुल्यांकन एवं 2607 का कौशल उन्नयन किया गया ।	16156	
11.	स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	94000	विभागों की प्रमुख सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स एवं डेटा को होस्ट करने हुत स्टेट डाटा सेंटर एवं क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना	कुल 28 विभागों की बेबसाईट एवं एप्लीकेशन का संचालन एवं संधरण किया जा रहा है ।	0	
12.	यूनिफाईड डेटा बेस परियोजना	राज्य स्तर पर लाभार्थियों का एकीकृत मास्टर डैटा बेस बनाना	100000	डेटा का एकत्रीकरण कर उनको एकीकृत करने के संसाधन जुटाना	योजा अप्रारम्भ	0	

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	जिला ई-गवर्नेस सोसायटी का संचालन	ई-गवर्नेस कार्यो के लिए जिला स्तर पर संचालन हेतु अमला उपलब्ध कराना	15000	27 जिला ई-गवर्नेस सोसायटी का संचालन करना	कुल 27 ई-जिला प्रबंधक को मानदेय, दूरसंचार व्यय, कार्यालयीन परिवहन एवं अन्य व्यय किया गया ।	0	
14.	मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना	विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ एवं उच्च शिक्षित युवाओं की सेवा योजनाओं के निर्माण, समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु प्राप्त करना	30000	40 कार्यालय को फेलोज की सेवाएं देना	43 मुख्यमंत्री सुशासन फेलोज की पदस्थापना कर शासकीय योजनाओं की समीक्षा, मूल्यांकन एवं संवर्धन का कार्य किया गया ।	6000	
15.	वाई-फाई सिटी की योजना	नागरिकों को सर्वाजनिक स्थलों पर नि:शुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना	12600	राज्य के प्रमुख क्षेत्रों/शहरों में 20 वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाना	वाई-फाई सिटी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य के पांच शहरों (रायपुर, बिलसपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं अंबिकापुर) में 19 सार्वजनिक सीानों में नागरिकों के लिए वाई-फाई के माध्यम से इन्टरनेट कनेक्टिविटी का संचालनप एवं संधारण	2600	
16.	स्वान परियोजना का विस्तारीकरण	स्वान नेटवर्क का विस्तार कर दूरस्थ क्षेत्रों में शासकीय कार्यालयों को जोड़ना	10000	सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन करना	योजना का डी.पी.आर. तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजा गया ।	0	